बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 256

अलग-अलग रुख

अर्थव्यवस्था को लेकर अलग-अलग रुख अपनाया जा रहा है और सत्ताधारी दल की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि उनकी अनदेखी करनी संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के आरंभ से ही यह स्पष्ट रहा है कि सरकार के लिए राजनीति अर्थव्यवस्था से ऊपर है। ऐसा 2014 में मोदी के लंबे चौड़े भाषण के बावजूद था। आज यह कहीं अधिक स्पष्ट है: अर्थव्यवस्था की महत्ता आज राजनीतिक संबद्धता के बुनियादी नियमों से भी कमतर रह गई है जहां संघ परिवार के लंबे समय से चले आ रहे नारों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप दलील दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी जनादेश हासिल किया है। जब इंदिरा गांधी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थीं। तब जनादेश और बड़ा था। इसके चलते ही उन्होंने वाम रुझान वाली आर्थिक नीति अपनाते हुए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया, प्रतिबंधात्मक श्रम कानून बनाए और तथा ऐसे ही अन्य कानून पारित किए। उन्होंने भू-कानूनों को भी कड़ा किया। अर्थव्यवस्था आज तक राजनीति को दी गई उस वरीयता की कीमत चुका रही है। क्या इतिहास अपने आपको दोहराएगा?

बड़े बदलाव टुकड़ों में नहीं आते हैं और फिलहाल काफी कुछ छिटपुट तरीके से हो रहा है। यह सब उस नई बहस का हिस्सा हो सकता है जिसमें राष्ट्रीय नागरिक पंजी द्वारा संभावित अशांति भी शामिल है। भाजपा चाहे जितनी दबदबे वाली पार्टी बन गई हो, घरेलू राजनीतिक हालात दर्शाते हैं कि केंद्र और राज्य के स्तर पर तस्वीर एकदम विरोधाभासी है। भाजपा के लिए चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ हिंदी प्रदेश में जीत सुनिश्चित करने के उसके प्रयास ने उसे तमाम तरह की अल्पसंख्यक आबादी के सामने ला खड़ा किया है। इसके परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वोत्तर में इनर लाइन जैसी परिवर्ती व्यवस्था अब स्थायी स्वरूप ले रही है और इसका विस्तार हो रहा है। इससे देश नये तरीके से बंट रहा है। असम में नये सिरे से समस्या शुरू हो गई है जबकि कश्मीर में आम जनता लगातार पांचवें महीने तमाम प्रतिबंधों से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक देशों ने जिन वजहों से अधिनायकवादी चीन पर भारत को तवज्जो दी थी और उसके साथ आपसी रिश्ते कायम किए उन पर भी अब सवालिया निशान लग गए हैं। अमेरिका और यूरोप में आलोचना की जा रही है जो आगे और बढ़ेगी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में प्रतिक्रिया नजर भी आने लगी है। कमजोर भारतीय अर्थव्यवस्था के चलते चीन से मिल रही चुनौती का सामना करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसने भारत की तरह अपनी गति नहीं खोई है। दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते भारत आकर्षक बाजार बना रहेगा लेकिन उसने जो गति खो दी उसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर आएगा। आर्थिक कूटनीति के मामले में हालात उलट गए हैं जिससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते। सन 2020 में अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार की अपेक्षा की जा सकती है लेकिन तत्काल पहले जैसी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने की राह में बड़ी बाधाएं हैं। वित्तीय क्षेत्र की दिक्कतें कायम हैं और छोटे और मझोले उपक्रम संघर्षरत हैं। कृषि के मोर्चे पर दिक्कत है और निर्यातक मुद्रा नीति के कारण परेशानी में हैं। वृहद आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो राजकोषीय स्थिति बुरी है क्योंकि केंद्र अपने बिल तक चुकाने की स्थिति में नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कुछ बुनियादी समस्या हैं जो कर के मोर्चे पर भी दिक्कतदेह बनी हुई हैं। चुनाव पूर्व कर दरों में कमी ने हालात और खराब किए। मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएं हैं और बहुत अधिक गुंजाइश नजर नहीं आ रही। जीएसटी राजस्व में कमी के कारण सरकार की निजी बेहतरी की प्रतिबद्धताएं अब मुश्किल में हैं। इनमें चुनाव पूर्व किसानों को धन राशि देने का वादा भी शामिल है। इन वादों पर अमल अपने साथ राजकोषीय फिसलन लाएगा और इसके लिए ऋण लेना पड़ सकता है जो जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्ज में इजाफा करेगा। परिवहन के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से भी अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला जबकि बिजली क्षेत्र में अव्यवहार्यता बरकरार है।

भाजपा की राजनीतिक दबदबे और संबद्धता के नियमों का पुनर्लेखन बताता है कि उसकी प्राथमिकताएं कितनी गलत हैं। ऐसे में शायद वापसी मुश्किल हो जाए। अनुमान यह है कि अगले आम चुनाव से पहले आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन अगर मौजूदा दिशा नहीं बदली गई तो ऐसे अनुमान गलत साबित होंगे। सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

बिनय सिन्हा

एक सांख्यिकीय संस्थान का दम तोड़ रहा वजूद

हालिया विवादों में उलझे एनएसएसओ को बदलते वक्त के हिसाब से अपना कामकाज दुरुस्त करने की जरूरत है। इसका विश्लेषण कर रहे हैं **सुनील के सिन्हा**

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट जारी न होने से उठे विवाद और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) की घरेलू उपभोग पर तैयार रिपोर्ट लीक होने से संबंधित विवादों से भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। ऐसे वक्त में यह बेहद जरूरी है कि एनएसएसओ के कामकाज पर एक नजर डाली जाए।

भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का विकास हमारी बेहद विशाल एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के बारे में विभिन्न मसलों से संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए किया गया था। इस प्रणाली की प्रभावी उपलब्धियों के बावजूद आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ती रही हैं। आंकड़ों का संग्रह, सारिणीकरण और उनकी व्याख्या की समस्याएं दूर करने के लिए 1961 में भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) का गठन किया गया। फिर रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक 12 जुलाई, 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग वजूद में आया।

एनएसएसओ को अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित घरेलू एवं उद्यम जगत से जुड़े व्यापक सर्वेक्षण करने का जिम्मा दिया गया।

सरकार ने दिवंगत प्रोफेसर पी सी महालनोबिस की सलाह पर एनएसएसओ का गठन 1950 में किया था। महालनोबिस उस समय नेहरू मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार थे। राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय के कुल जोड़ की गणना के लिए उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों में बड़ी खामियां पाई थीं। इन कमियों को दूर करना ही एनएसएसओ का मुख्य मकसद था। अप्रैल 1961 में सांख्यिकी विभाग का गठन किया गया और एनएसएसओ इसका अंग बना दिया गया। अक्टूबर 1999 में एनएसएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक संबद्ध कार्यालय बन गया।

एनएसएसओ ने अपने सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत अक्टूबर 1950 से मार्च 1951 के दौरान ग्रामीण इलाकों में विभिन्न मुद्दों के बारे में पड़ताल से की थी। दसवें दौर का सर्वेक्षण होने तक एनएसएसओ पूरी तरह व्यवस्थित हो चुका था। संसद में 1959 में अधिनियम पारित होने के बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को भी वैधानिक दर्जा मिल गया। इसकी आम स्वीकृति इससे पता चलती है कि सरकारी संगठन एवं स्वायत्त संस्थान जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए एनएसएस की सर्वे पद्धति में रुचि दिखाते थे।

सांख्यिकी मंत्रालय के एक प्रशासकीय आदेश के मुताबिक मई 2019 में एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के साथ मिलाकर नया संगठन एनएसओ बना दिया गया। हालांकि एनएसएसओ के चार प्रकोष्ठ यथावत बने रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि एनएसएसओ को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पेश करने को लेकर पहले जो थोड़ी-बहुत स्वायत्तता हासिल थी, अब वह क्षीण हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब भी कार्य-समूह एवं तकनीकी समितियां और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदा भूमिका विशुद्ध रूप से तकनीकी ही हैं। एनएसएसओ की कुछ हालिया रिपोर्ट जारी होने के पहले मीडिया में लीक होने के बाद कई तरह के आरोप लगाए गए थे।

अगले साल एनएसएसओ 70 साल पुराना संगठन हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का एक शुभचिंतक होने और खुद इस व्यवस्था का 37 वर्षों तक हिस्सा रहने वाले शख्स के नाते मैं आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ सुझाव रख रहा हूं:

- सत्ता पर काबिज सरकार को आंकड़ा संग्रह का काम प्राथमिकता में रखना चाहिए और संक्षिप्त अवधि की अनुबंधित नियुक्तियों से परहेज करना चाहिए। आंकड़े जुटाने के काम में लगे नियमित कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि किए जाने से रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। अधिक स्वायत्तता के लिए एनएसएसओ को सांख्यिकीय आयोग के मातहत रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सांख्यिकीय आयोग को कानूनी रूप से अधिक सशक्त भी बनाया जाना चाहिए।
- आंकड़े जुटाने के काम में लगे कर्मचारियों को मौजूदा समय की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का अंग होना चाहिए।
- अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का नाम बदलकर सहयोगी सांख्यिकीय सेवा कर दिया जाना चाहिए। इसमें डेटा संग्राहकों को भी जगह दी जानी चाहिए।
- डेटा संग्राहकों की संख्या एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के नमूना आकार के आधार पर तय की जा सकती है। उन्हें उन राज्यों में तैनात करना चाहिए जहां के वे निवासी हों और वहां की स्थानीय भाषा से भी परिचित हों।
- एनएसएसओ दरों, अनुपात एवं प्रतिशत के संदर्भ में पैमानों का आकलन करता रहा है लिहाजा एनएसएस के हालिया सर्वेक्षणों का मौजूदा नमूना आकार बुनियादी मानकों के बारे में विश्वसनीय अनुमान देने के लिए पर्याप्त है।
- एनएसएसओ को अब पैनल नमूना दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसा कि भारत के महापंजीयक (आरजीआई) में नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के लिए किया जा रहा है। नमूना डिजाइन में इस तरह का बदलाव लाने के लिए कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत पड़ सकती है।
- एनएसओ के सर्वे डिजाइन एवं शोध प्रभाग (एसडीआरडी) के लिए अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अभी तक वे बुनियादी तौर पर सर्वे सूची के डिजाइन, सारिणीकरण योजना, क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने, प्रशिक्षण और संग्रहीत आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में ही लगे हुए हैं। उन्हें यूनिट स्तरीय डेटा पर आधारित अधिक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए।
- एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन प्रभाग को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण एवं औचक निगरानी के अलावा पर्यवेक्षकों की यात्रा डायरी के विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

(लेखक एनएसएसओ के पूर्व महानिदेशक एवं सीईओ हैं)

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

येदियुरप्पा और उनके पुत्र की मेहनत से कर्नाटक में जीत

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

आलोचना करने वाले फिलहाल खामोश हैं। चुनौती देने वालों ने भी अपनी तलवारें कम से कम अभी तो अपनी म्यान में रख ली हैं। बीएस येदियुरप्पा ने अपने मित्रों और खासतौर पर अपने परिवार की बदौलत ऐसी वापसी की है जो खुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर कई के लिए ईर्ष्या की वजह बन गई होगी। ऐसे लोगों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। फडणवीस महाराष्ट्र में मिली हार से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह देखना चुभा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों से येदियुरप्पा का खड़े होकर स्वागत करने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक उपचुनाव में जीत के बाद राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह स्थिर हो गई है।

यह सच है कि येदियुरप्पा ने उपचुनाव जीतने में अपनी सारी ताकत झोंक दी। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में 224 में से 105 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 78 और जनता दल सेक्युलर को 37 सीटें मिली थीं। येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का प्रयास किया लेकिन वह नाकाम रहे और आखिरकार उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और भाजपा को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। परंतु येदियुरप्पा के लिए यह व्यक्तिगत झटका था। जब उन्हें 2016 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था तो उन्हें काफी गुटबाजी संभालनी पड़ी। कुरुबा (गड़रिया) समुदाय के के एस ईश्वरप्पा ने अपनी जाति के लोगों को एकजुट किया और लिंगायत (येदियुरप्पा) और वोक्कालिंगा (एचडी देवेगौड़ा) दोनों समुदायों से मुकाबला किया जा सके। वोक्कालिंगा सदानंद गौड़ा और लिंगायत जगदीश शेट्टार को कई शिकायतें थीं। उन्हें बीएल संतोष के रूप में एक सुनने वाला मिला जो आरएसएस और भाजपा के बीच समन्वयक थे। इन बातों से निजात पाना आसान नहीं था। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनावों में येदियुरप्पा को सांत्वना से संतुष्ट होना पड़ा, हालांकि उन्हें लगा था कि वह प्रथम आए हैं।

अब हालात बदल चुके हैं। कुछ सप्ताह पहले तक कर्नाटक और महाराष्ट्र में खास अंतर नहीं था। दोनों राज्यों में किसी तरह सत्ता चल रही थी। लेकिन फडणवीस फिसल गए जबकि येदियुरप्पा कर्नाटक के मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे कि यह मतदान विधायक (ये कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से भाजपा में आए विधायक थे) के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए हो रहा है।

> मुख्यमंत्री कम ही इतनी मेहनत करते नजर आते हैं। वह हर विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन बार गए। उन्होंने कुल 50 यात्राएं कीं।

कर्नाटक में जीत के पीछे क्या वजह रही? यकीनन येदियुरप्पा की मेहनत। मुख्यमंत्री कम ही इतनी मेहनत करते नजर आते हैं। वह हर विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन बार गए। उन्होंने कुल 50 यात्राएं कीं। भाजपा पुराने मैसूर में जीती जो वोक्कालिंगा समुदाय और जनता दल सेक्युलर तथा कांग्रेस का गढ़ है। मांड्या जिले की कृष्ण राजा पेट सीट जहां भाजपा को इससे पहले के चुनावों में 10,000 वोट से ज्यादा नहीं मिले वहां जनता दल सेक्युलर के पूर्व विधायक नारायण गौड़ा इस बार 9,000 से अधिक मतों से जीते। वह उन 17 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा की सरकार बनने की राह आसान की थी। यह जीत दोहरे महत्त्व की है। एक तो यहां चुनाव प्रबंध की कमान येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजयेंद्र के हाथ में थी। निवर्तमान कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी क्षेत्र की वरुणा सीट से चुनाव लड़े थे। विजयेंद्र उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने यह सीट बीएल संतोष समर्थित प्रत्याशी को दे दी। कांग्रेस ने सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र को उतारा जो यहां से जीत गए। परंतु आखिरकार केआर पेट सीट छीनकर विजयेंद्र ने अपनी हैसियत दर्ज कराई।

येदियुरप्पा का कार्य क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र शिमोगा है। परंतु वह केआर पेट में पैदा हुए थे। विजयेंद्र ने अपनी नीति में इस बात को शामिल किया। 2 लाख मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में करीब 93,000 वोक्कालिंगा मतदाता हैं। तार्किक रूप से देखें तो लिंगायतों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के लिए यहां जाति का कार्ड खेलना असंभव था। इसके बजाय विजयेंद्र ने अपने प्रचार में यह छवि पेश की कि वह अपने पिता की जमीन पर वापस आए हैं। लोगों ने कहा कि भाजपा पुराने मैसूर में कभी नहीं जीत सकती। जवाब में विजयेंद्र कहते कि अगर अमित शाह भाजपा को बंगाल में जिता सकते हैं तो भाजपा यहां भी जीत सकती है।

एक बात को बिल्कुल ठीक-ठीक समझने की आवश्यकता है कि कर्नाटक उपचुनावों में भाजपा को जीत मिली, उम्मीदवारों को नहीं। येदियुरप्पा के आलोचक अब अपना ध्यान शासन-प्रशासन की कमियों पर केंद्रित करेंगे लेकिन विजयेंद्र ने भाजपा के लिए एक ऐसी राजनीतिक राह खोली है जो अब तक बंद चली आ रही थी। कर्नाटक के राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए विजयेंद्र तथा पार्टी के अन्य युवा नेताओं पर आने वाले दिनों में नजर रखनी होगी।

कानाफूसी

आजाद का दल

एक अरसे तक शांत रहने के बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अब अपने नाम से उपनाम रावण हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि वह बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए सक्रिय राजनीति में आएंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आजाद को भाजपा का एजेंट भी कह चुकी हैं। यह बात अलग है कि आजाद ने हमेशा उनका नाम आदर से लिया है। आजाद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है। आजाद लखनऊ में एक रैली करके अपने राजनीतिक दल की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टी का मुख्यालय भी लखनऊ होगा। उनकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा से बसपा, सपा और कांग्रेस के दलित नेताओं के बीच संत्रास उत्पन्न होना लाजिमी है। इससे दलित मतों में जो बंटवारा होगा वह भाजपा के काम अवश्य आ सकता है।

रहस्यमय अनुपस्थिति

राज्य सभा सचिवालय ने गुरुवार को उन 16 सांसदों के नाम जारी किए जो बुधवार को उच्च सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक पर मतदान के दौरान अनुपस्थित थे। इनमें शिवसेना के तीनों सांसदों के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार में से दो सांसद शामिल थे। राकांपा प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने जहां विधेयक के खिलाफ मतदान किया, वहीं मजीद मेनन और वंदना चव्हाण अनुपस्थित रहे। अन्य अनुपस्थित सांसदों में भाजपा के चुन्नीभाई गोहेल और अनिल बलूनी शमिल हैं। ये दोनों ही अस्वस्थ हैं। सपा के बेनी प्रसाद वर्मा और स्वतंत्र सांसद अमर सिंह भी बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो सके। तृणमूल कांग्रेस के के डी सिंह भी अनुपस्थित रहे। परंतु सबसे रहस्यमय अनुपस्थिति थी बसपा के दो सांसदों राजाराम और अशोक सिद्धार्थ की। दिलचस्प बात यह है कि जनता दल (सेक्युलर) के इकलौते सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी ने अपनी पार्टी के प्रमुख एच डी देवेगौड़ा की तरह बहस के दौरान विधेयक का विरोध किया लेकिन मतदान के वक्त वह सदन में नजर नहीं आए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के धर्मपुरी श्रीनिवास भी अनुपस्थित रहे जबकि पार्टी के अन्य सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।

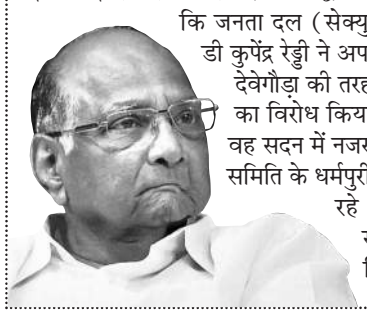

आपका पक्ष

रेबीज संक्रमण के रोकथाम के हों उपाय

हाल में जारी नैशनल हेल्थ प्रोफाइल के आंकड़ों के अनुसार रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मरने वालों की संख्या इससे संक्रमित होने वालों की संख्या के समान रही है। रेबीज से होने वाली मौत के ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है। रेबीज वायरस के वाहक सामान्यत: संक्रमित कुत्ते, घोड़े, बंदर होते हैं जिनके संपर्क में लोग रहते हैं। रेबीज संक्रमण के शिकार होने के सबसे अधिक मामले कुत्ते के काटने के होते हैं। कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाएं उनकी बढ़ती आबादी के कारण हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधित वैश्विक 10 प्रमुख संकट की सूची में रेबीज वायरस द्वारा होने वाले संक्रमण भी शामिल है। इस पर वर्ष 2019 में सभी हितधारकों को फौरन ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।

दुनिया भर में 28 सितंबर को विश्व ऐंटी रैबीज दिवस मनाया जाता है। भारत में इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। इसकी रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने होंगे। कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय नसबंदी रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। लेकिन समुचित प्रशिक्षण के अभाव एवं राशि की कमी जैसी बुनियादी समस्याओं के कारण यह अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त दिक्कतों को दूर करना होगा। आबादी वाले क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। रेबीज संक्रमित व्यक्ति के समुचित इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऐंटी रेबीज दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

रेबीज के इलाज के लिए अस्पतालों में ऐंटी रेबीज की दवाई पर्याप्त मात्रा में हो

ऋषभ देव पांडेय, जांजगीर चांपा

रोजगार सृजन के हों ठोस उपाय

पिछले माह एक रिपोर्ट आई थी कि देश में बेरोजगारी दर पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि सरकार ने इस आंकड़े को खारिज कर दिया था। लेकिन देश में बेरोजगारी की समस्या बरकरार है और रोजगार सृजन भी बेरोजगारी को दूर करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। हाल में टीमलीज द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में रोजगार के अवसरों में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 क्षेत्रों में से सात में नौकरी गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद है जबकि नौ क्षेत्रों में कमी आने की आशंका है। देश में फिलहाल आर्थिक सुस्ती छाई हुई है। वाहन क्षेत्र में मंदी से कई लोग बेरोजगार भी चुके हैं। वहीं आंकड़ों को देखा जाए तो 19 में केवल सात क्षेत्रों में 7 प्रतिशत की वृद्धि दिख रही है जबकि नौ क्षेत्रों में कमी भी दिखाई पड़ रही है। अत: सरकार को रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

अंकित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।